दिनांक 9 अगस्त, 2019 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह के अवसर पर माननीया राज्यपाल–सह–कुलाधिपति के अभिभाषण के मुख्य बिन्दुः–

- विश्व आदिवासी दिवस के अवसर के पावन अवसर पर सभी को जोहार और इस पावन दिवस की बधाई।
- मुझे अवगत कराया गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार जनजातीय समुदाय के किसान एवं वैज्ञानिकों के समागम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय का यह प्रयास सार्थक पहल होगा। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाने वाला इस विश्वविद्यालय का राज्य के कृषि विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष आज के दिन अर्थात 9 अगस्त को International Day of the World's Indigenous Peoples के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाये जाने का मूल उद्देश्य उनके संरक्षण के साथ इस समुदाय का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके अंदर निहित संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है।
- जानकारी के अनुसार, दुनिया में अनुमानित 370 मिलीयन आदिवासी लोग हैं, जो करीब 90 देशों में रह रहे हैं। वे दुनिया की आबादी के 5% हिस्से से भी कम है, जो विश्व की

अनुमानित 7 हजार भाषाओं में बात करते हैं और 5 हजार विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- किसी भी देश में निवास करने वाले वहां के मूल निवासी को उक्त देश की ऐतिहासिक धरोहर कहा जाता है, जो उस देश की वास्तविक संस्कृति को प्रदर्शित करते है। इन लोगों का संरक्षण करना सरकार और अन्य नागरिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जनजातीय लोगों को विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत जनजातीय उप–योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है । इन सहायताओं का मूल प्रयोजन आदिवासी लोगों के पारिवारिक आय सृजन में बढ़ोतरी के लिए कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गांव, लघु उद्योगों तथा न्यूनतम आवश्यकता संबंधी कार्यक्रमों से बढ़ावा देना है।

- भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास के समन्वित और योजनाबद्ध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए चलाई जा रही समग्र नीति, योजना और समन्वयन के लिए भारत सरकार का एक नोडल मंत्रालय है। प्रसन्नता का विषय

है कि वर्त्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री झारखण्ड के ही सपूत हैं।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों के लिए समग्र नीति, आयोजनों और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय रूप में कार्यरत है, जो कार्यक्रमों और इस समुदाय की नीति, आयोजन, निगरानी, मूल्यांकन आदि के विकास की योजनाओं में समन्वय के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व निभाता है।
- केंद्र एवं राज्य सरकार के भरपूर एवं सतत प्रयासों के बाद भी भारतीय समाज का आदिवासी समुदाय कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी हजारों आदिवासी लड़कियां गरीबी में और शिक्षा में कमी के कारण दूसरे के घर में काम करने को मजबूर हैं।
- देश की कई फीसदी लडकियां निरक्षर हैं, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा को बुनियादी हक बना दिया गया है। इसके बावजूद विशेषकर समाज के आदिवासी एवं दलित समुदाय के लडकियों की शिक्षा पर व्यापक विचार और रणनीति बनाने की जरूरत है। हमारे बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2019 के मानद सदस्य कुलपति डॉ. कुरील भी मौजूद है। आशा करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप - 2019 में आदिवासी एवं दलित समुदाय के हितों की बातों को विस्तार से समाहित किया जायेगा।
- गत दो वर्षों में विश्वविद्यालय के अधीन तीन नये कृषि महाविद्यालय एवं एक-एक Dairy technology, fishery

science, Garden एवं Agriculture Engineering विषयों के 7 महाविद्यालयों के जुड़ने से दो वर्षो में UG Course में करीब 240 तथा PG Courses में 52 जनजातीय विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। इसके बावजूद कृषि विषयों में जनजातीय समुदाय के सदस्यों की संख्या में कमी चिंताजनक है। मेरा मानना है कि समुदाय के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक कार्यों के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास हो।

- इस विश्वविद्यालय ने राज्य में प्रथम अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव का सफल आयोजन से एक नई मिसाल पेश की है। मेरा सुझाव होगा कि विश्वविद्यालय के स्थानीय जनजातीय छात्र–छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की सोच को बढ़ावा एवं सांस्कृतिक एकता को कायम तथा संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ICAR विकास निधि से कृषि विश्वविद्यालयों का अखिल भारतीय जनजातीय युवा महोत्सव का आयोजन हो।
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित शोध तकनीकों से राज्य के कृषि विकास को तेजी मिली है। विश्वविद्यालय में ICAR के सौजन्य से संचालित विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के जनजातीय उपयोजना के अधीन शोध तकनीकों के हंस्तांतरण कार्यक्रमों से जनजातीय किसानों के आय सृजन में बढ़ोतरी के कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसल किस्मों एवं राष्ट्रीय स्तर के उन्नत किस्मों के जनजातीय किसानों के बीच अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण एवं प्रक्षेत्र दिवस के माध्यम से खेतों में ही

तकनीकी ज्ञान देने से जनजातीय किसानों को कुछ लाभ मिला है।

- राज्य के जनजातीय किसानों के आजीविका का पशुपालन सर्वाधिक प्रमुख साधन रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा मुर्गी की झारसीम प्रजाति, सूकर की झारसुक प्रजाति तथा बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल को विकसित किये जाने से जनजातीय किसानों के आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों के तकनीकी हस्तक्षेप एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ग्रामीण स्तर पर जनजातीय किसानों को लाभ मिल रहा है।
- अवगत कराया गया कि जनजातीय उपपरियोजना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा कांके प्रखंड के नगड़ी एवं एकम्बा गाँव को गोद लेकर जनजातीय किसानों की आय में वृद्धि लाने हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है।
- कृषि वानिकी भी जनजातीय किसानों के जीवन का मुख्य आधार है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि वानिकी के तहत विभिन्न जिलों के जनजातीय किसानों के बीच बांस की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा तथा रांची के नगड़ी प्रखंड में एलोवेरा विलेज की स्थापना से जनजातीय किसानों को आय सृजन का अवसर मिला है।
- विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निदेशालय के प्रसार कार्यक्रमों एवं रणनीतिक कार्यकलापों से केंद्र एवं राज्य सरकार के जनजातीय विकास कार्यक्रमों को तेजी से अमल में लाया जा रहा। निदेशालय के **Farmers First Programme** के माध्यम से जनजातीय किसानों की आजीविका एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिला है।

- जिला स्तर पर संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण के तहत जनजातीय युवा–युवतियों को स्वरोजगार आधारित नियमित प्रशिक्षण, जनजातीय किसानों के खेतों में तकनीकी परीक्षण से तकनीकों को बढ़ावा देने, अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा तथा अन्य कृषि विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्षमता तथा कौशल विकास को बल मिला है।
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के जनजातीय लोगों के हित में शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम चलाये जा रहे है। विश्वविद्यालय को जनजातीय से जुड़े कार्यो का डाटा संग्रह, प्रभावों का विश्लेषण और बेहतर भावी रणनीति तैयार करनी चाहिये।
- आशा करती हूँ कि इस समारोह के आयोजन से जनजातीय समुदाय के सामाजिक उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता विषय पर चर्चा से समाज के विकास को गति मिलेगी।

जय हिन्द! जय झारखण्ड!